

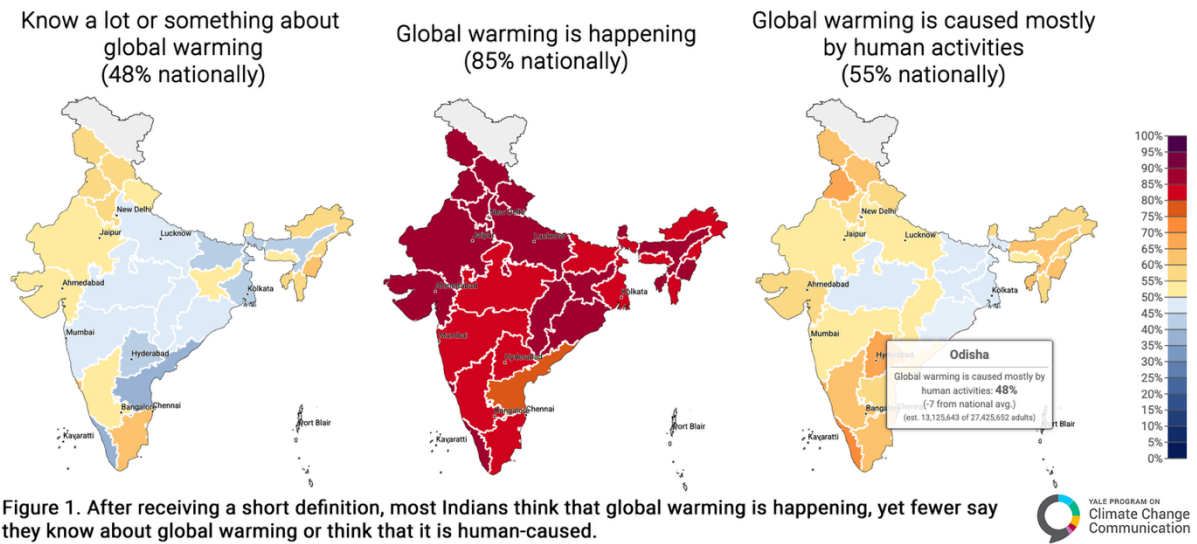
प्रिय मित्रों,

हमें [इंडिया क्लाइमेट ओपिनियन मैप्स](#) के ताज़ा अपडेट की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह हमारा इंटरैक्टिव टूल है जो भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 34 तथा 634 जिलों में लोगों के ग्लोबल वार्मिंग के अनुभव, इसके बारे में उनकी मान्यताओं, नीतियों के समर्थन और जोखिम को लेकर उनकी सोच को नक्शों के ज़रिए दिखाता है। इस अपडेट में 2026 तक का नया, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वेक्षण डेटा शामिल किया गया है। यह डेटा हमारे सहयोगी सीवोटर ने जुटाया है। ग्लोबल वार्मिंग को जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज भी कहा जाता है।

### मुख्य बातें

- ग्लोबल वार्मिंगकी परिभाषा सुनने के बाद, हर राज्य और जिले में 75% से अधिक भारतीयों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और वे इसे लेकर चिंतित हैं। लगभग इतने ही लोगों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग से भारत के लोगों को नुकसान पहुँचेगा।
- दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक लोग बताते हैं कि उन्होंने खुद भीषण गर्मी (लू) और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का सामना किया है। उनका यह भी मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग से उन्हें, उनके परिवारों और उनके समुदायों को नुकसान होगा।
- मध्य और पूर्वी भारत में बहुत कम लोग कहते हैं कि उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी है और वे मानते हैं कि यह इंसानी गतिविधियों की वजह से हो रही है। इससे साफ़ पता चलता है कि लोगों में जलवायु को लेकर बुनियादी समझ की कमी है।
- निजी अनुभवों और जोखिम को लेकर सोच में क्षेत्रीय अंतर होने के बावजूद, अधिकांश भारतीय कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा उनके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही, वे रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) और ग्लोबल वार्मिंग पर शिक्षा का भी पूरा समर्थन करते हैं।

भारत में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी का स्तर कम है—मध्य, पश्चिमी और पूर्वी राज्यों में आधे से भी कम लोग कहते हैं कि वे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत कुछ या थोड़ा-बहुत जानते हैं (चित्र 1)। हालांकि, जब ग्लोबल वार्मिंग की एक छोटी सी परिभाषा दी जाती है, तो अधिकांश भारतीयों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है; यह आंकड़ा आंध्र प्रदेश में 80% से लेकर दिल्ली में 92% के बीच है (चित्र 1)। फिर भी, जलवायु से जुड़ी बुनियादी समझ (क्लाइमेट लिटरसी) में बड़ी कमियां बनी हुई हैं। कई भारतीय, विशेष रूप से मध्य और पूर्वी भारत के लोग, यह नहीं समझते कि ग्लोबल वार्मिंग इंसानी गतिविधियों की वजह से हो रही है—उदाहरण के लिए, बिहार (45%), मध्य प्रदेश (47%), ओडिशा (48%) और पश्चिम बंगाल (49%) में 50% से भी कम लोग मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इंसानों के क्रियाकलापों के कारण हो रही है (चित्र 1)।



हम यह भी पाते हैं कि देशभर में भारतीय ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बेहद चिंतित हैं। हर राज्य और जिले में तीन-चौथाई से अधिक भारतीयों का कहना है कि वे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित हैं (चित्र 2), हालांकि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में यह चिंता थोड़ी अधिक है। नुकसान की आशंका भी उत्तर भारत में ज्यादा देखी गई है, जहाँ भीषण गर्मी का प्रकोप अधिक रहता है। उदाहरण के लिए, उत्तरी राज्यों में हरियाणा के 86% और दिल्ली तथा पंजाब दोनों के 85% लोगों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग से उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुँचेगा, जबकि दक्षिणी राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह आंकड़ा क्रमशः 63% और 66% है (चित्र 2)। इससे भी बड़ी संख्या में हरियाणा (86%), दिल्ली (87%) और पंजाब (88%) के लोग यह भी मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से उनके समुदाय के लोगों को नुकसान होगा, जबकि दक्षिणी राज्यों कर्नाटक (63%), आंध्र प्रदेश (66%) और तेलंगाना (67%) में यह मानने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम है।

इसके अलावा, तटीय दक्षिण-पश्चिमी राज्य केरल में, जहाँ [हाल के वर्षों में भीषण बाढ़ आई है](#), 91% लोगों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग से उनके समुदाय के लोगों को नुकसान होगा (चित्र 2)। अलग-अलग राज्यों में लोगों के अपने जोखिम को लेकर सोच में अंतर होने के बावजूद, देशभर में 85% लोग और किसी भी राज्य या जिले में कम से कम 74% लोग मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से भारत में कुल मिलाकर लोगों को नुकसान होगा (चित्र 2)।

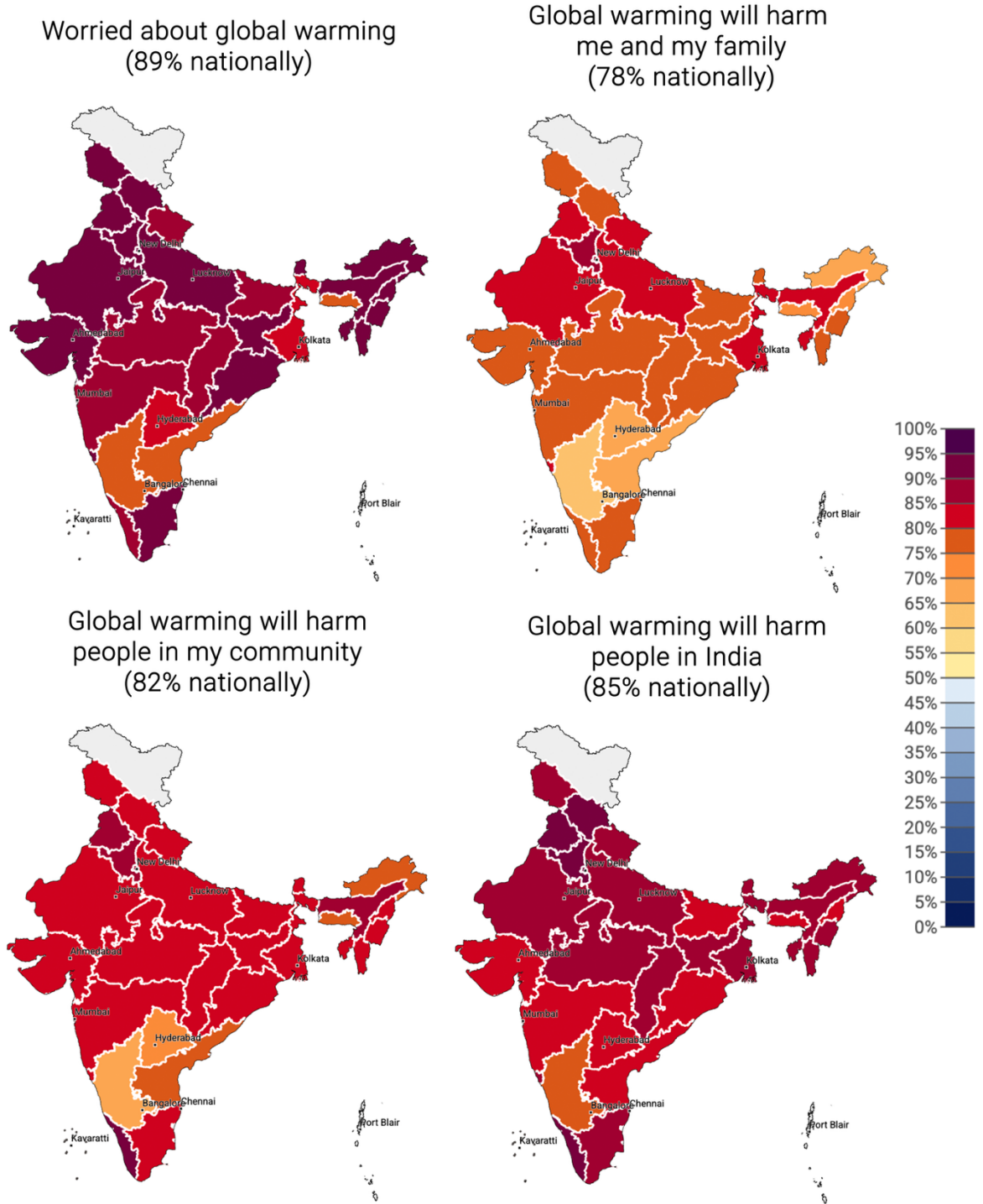


Figure 2. Across the country, Indians are worried about global warming, but more North Indians think it will harm them, their families, and their communities.



इसी तरह, ग्लोबल वार्मिंग और चरम मौसमी घटनाओं के अपने निजी अनुभवों को लेकर भी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच अंतर दिखाई देता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में केवल 59% लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को महसूस किया है, जबकि उत्तरी राज्यों हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में यह आंकड़ा क्रमशः 94% और 95% है

(चित्र 3)। उत्तर-दक्षिण का यह अंतर भीषण गर्मी (लू) के निजी अनुभवों में भी दिखता है, जहाँ हरियाणा (80%), राजस्थान (79%) और ओडिशा (79%) में भारी संख्या में लोग बताते हैं कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में भीषण लू का सामना किया है। इसके विपरीत, केरल में केवल 52% और तमिलनाडु में 55% लोग ही ऐसा कहते हैं (चित्र 3)।

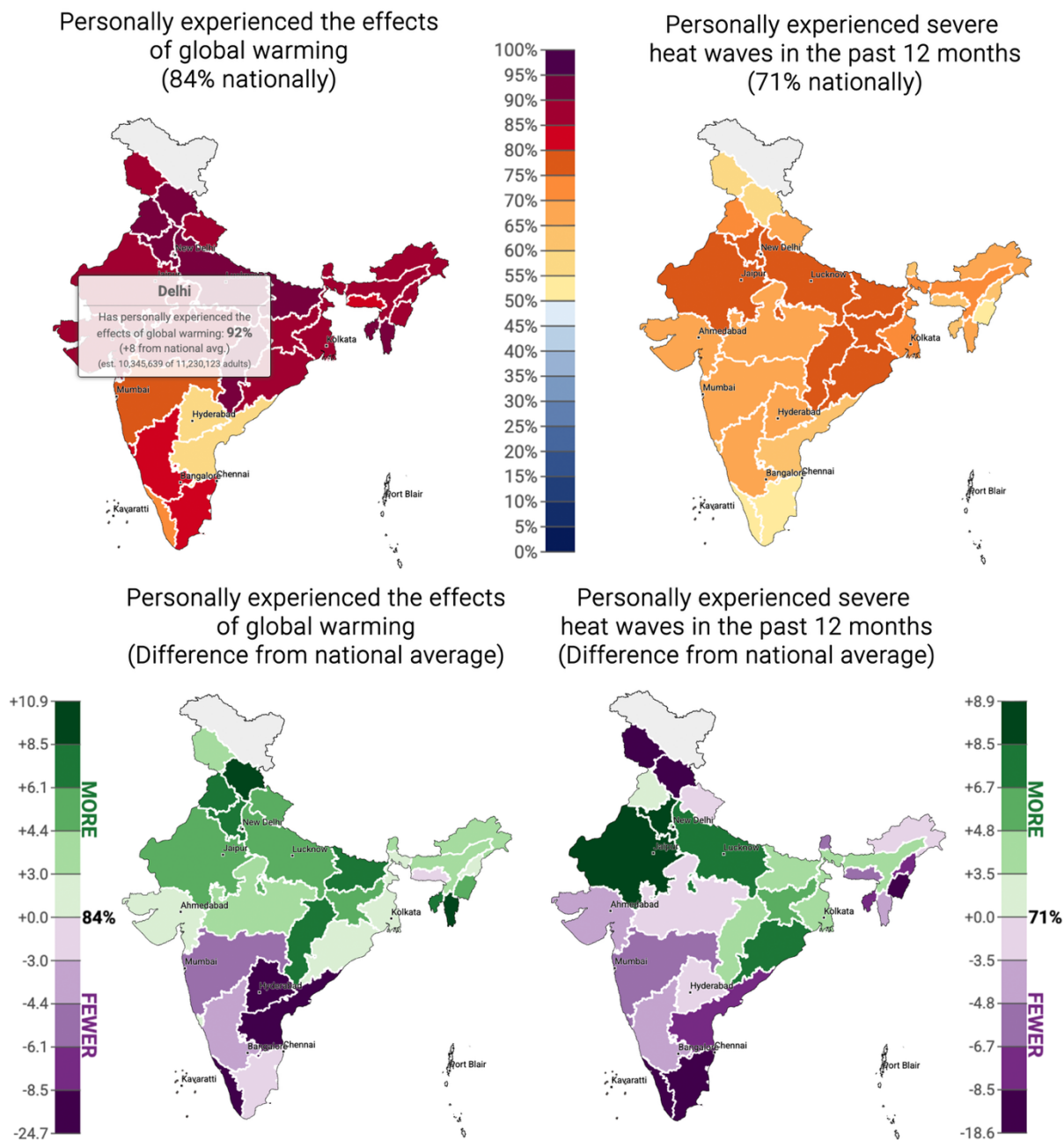
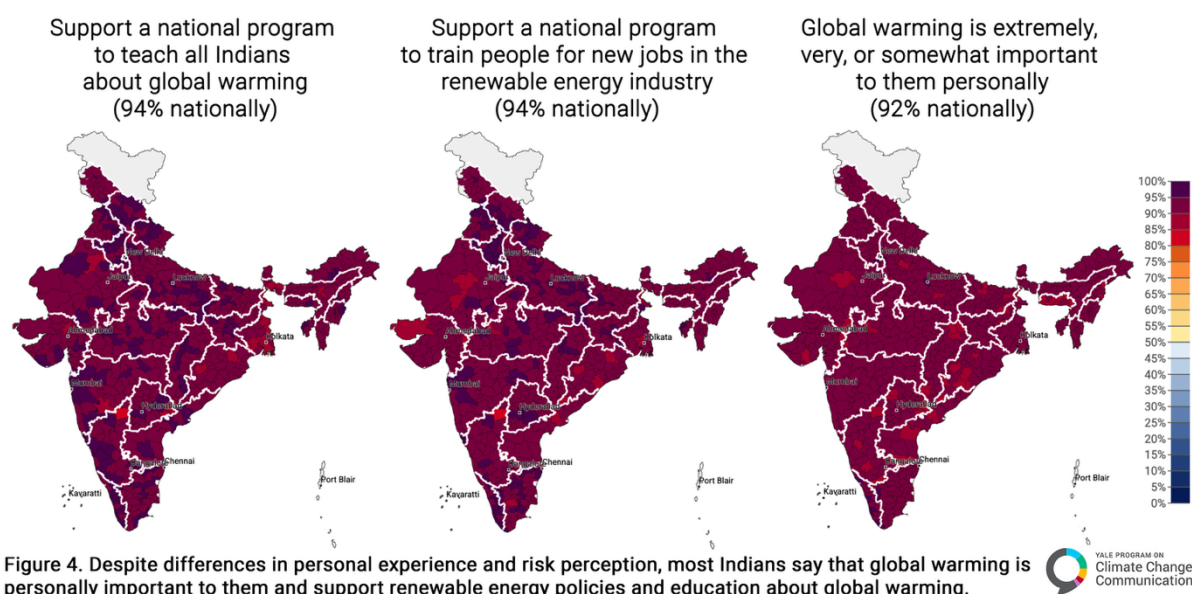


Figure 3. More people in northern vs. southern India report having personally experienced the effects of global warming and severe heat waves.



हमारे मैप्स ज़िला स्तर पर भी परिणाम दिखाते हैं, जिससे राय में भौगोलिक अंतर को बारीकी से समझा जा सकता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग और चरम मौसम के निजी अनुभव

उत्तर भारत में अधिक देखे जाते हैं, फिर भी देशभर में अधिकांश भारतीय कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा उनके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है। वे रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) से जुड़ी नीतियों और ग्लोबल वार्मिंग पर शिक्षा का भी पूरा समर्थन करते हैं। 94% भारतीय, और किसी भी राज्य या ज़िले में कम से कम 83% लोग, को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूक करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नौकरियों के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करते हैं (चित्र 4)। इसी प्रकार, 92% भारतीय-और किसी भी राज्य या ज़िले में कम से कम 85% लोग-कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग उनके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है (चित्र 4)।

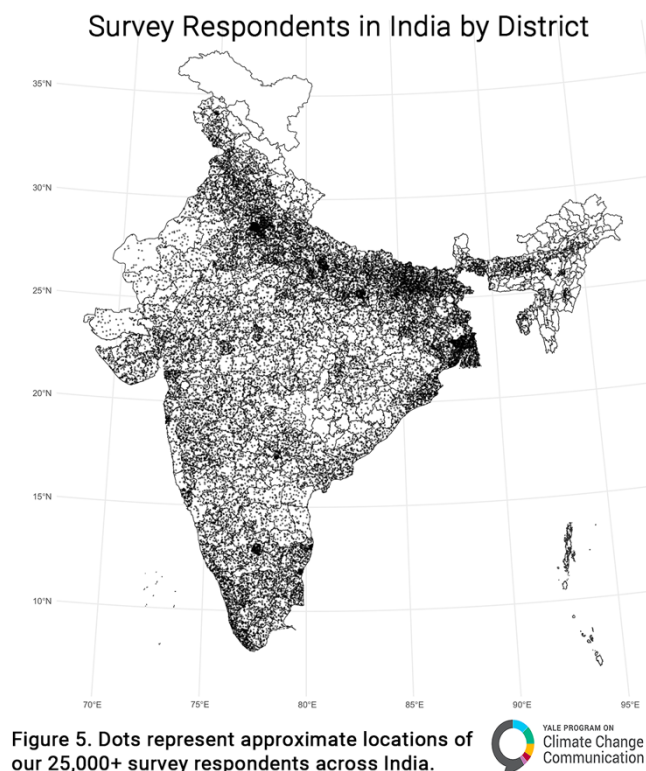


दुनिया में जलवायु के लिहाज से सातवाँ सबसे संवेदनशील देश और ग्रीनहाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक होने के नाते, यह समझना बेहद ज़रूरी है कि भारतीय ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह महसूस करते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं और वे किन जलवायु समाधानों का समर्थन करते हैं। जनमत के ये मैप्स भारत में 'स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज' (SAPCCs) यानी जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं को तैयार करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं।

## शोध-विधियां (मेथड्स)

नक्शों में दिए गए अनुमान एक सांख्यिकीय मॉडल (स्टैटिस्टिकल मॉडल) पर आधारित हैं, जिसमें मल्टीलेवल रिग्रेशन विद पोस्ट-स्ट्रेटिफिकेशन (एमआरपी) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मॉडल 2022 से 2026 तक के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वेक्षण डेटा ( $n > 25,000$ , चित्र 5) को जनसांख्यिकीय और भौगोलिक विशेषताओं-जैसे लिंग,

आयु, जाति, शहरीकरण का स्तर, शिक्षा और [जलवायु संवेदनशीलता](#) के साथ जोड़ता है, और परिणामों को भौगोलिक रूप से संतुलित (weight) करने के लिए भारतीय जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करता है (हाउ एवं अन्य 2015; मिल्डेनबर्गर एवं अन्य 2016; 2017)। अनिश्चितता की सीमाएं (uncertainty ranges) बूटस्ट्रैप सिमुलेशन का उपयोग करके 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल (विश्वसनीयता अंतराल) पर आधारित हैं। यह दर्शाती है कि यह मॉडल राज्य स्तर पर लगभग  $\pm 7$  प्रतिशत अंक और ज़िला स्तर पर लगभग  $\pm 8$  प्रतिशत अंक तक सटीक है। इस प्रकार की त्रुटि सीमाओं (error ranges) में मूल राष्ट्रीय सर्वेक्षणों की अंतर्निहित त्रुटि भी शामिल है, जो आमतौर पर  $\pm 3$  प्रतिशत अंक होती है।



अधिक जानकारी के लिए [मैथोडोलॉजी](#), [सर्वेक्षण के प्रश्न](#) और [FAQ टैब](#) देखें।

हमारी [वेबसाइट](#) पर इन मैप्स को देखें।